



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 7, 2004/आश्विन 15, 1926

No. 165]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2004/ASVINA 15, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 अक्टूबर, 2004

सं. टीएएमपी/41/2004-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी संदर्भ सं. पी आर-14019/20/2004-पीजी दिनांक 23 अगस्त, 2004 का अनुपालन करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा 13 फरवरी, 1992 से 31 अगस्त, 2003 तक की अवधि में विशाखापत्तनम् न्यास में मैग्नीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार निर्धारित करने के प्रकरण में संलग्न आदेशानुसार निर्णय देती है।

विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास

आवेदक

आदेश

(अक्टूबर, 2004 के पहले ही दिन पारित)

यह प्रकरण फरवरी, 1992 से अगस्त, 2003 तक की अवधि में विशाखापत्तनम् न्यास (वीपीटी) में मैग्नीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार निर्धारित करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी संदर्भ सं. पीआर-14019/20/2004-पीजी दिनांक 23 अगस्त, 2004 के आधार पर आरम्भ किया गया है।

2. पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि 1992 की याचिका सं. 17423 और 17424 में दिनांक 18 मार्च 2004 को माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में केन्द्रीय सरकार को निदेश दिया है कि वह विशा.प.न्यास के साथ-साथ याचिकाकर्ता मेसर्स सरावगी कम्प.(प्रा.) लिमि. को अवसर प्रदान करते हुए, 1992 के बाद (की अवधि के लिए विशा.प.न्यास में मैग्नीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार संबंधी समुचित दरमान पर विचार करे और निर्णय ले।

3.1. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इसी प्रकार की स्थितियों में केन्द्र सरकार ने, 1986-1992 की अवधि में विशा.प.न्यास में मैग्नीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार के निर्धारण से संबंधित प्रकरण को टीएएमपी को आन्तरित करते हुए 2 अगस्त 1998 को एक आदेश पारित किया था।

3.2. सरकारी आदेश के अनुपालन में, इस प्राधिकरण ने सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इस प्रकरण को हाथ में लिया और इस प्रकरण को निपटाते हुए 8 दिसम्बर 1999 को एक आदेश पारित किया। उक्त आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा स्थापित कुछ मुख्य सिद्धांत संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

- (i) अतिरिक्त अयस्क प्रहस्तन श्रमिकों (ओएचएल) की लागत, लौह अयस्क सहित मशीनों द्वारा प्रहस्तित सभी अयस्क के साथ गिनी जानी है।
- (ii) श्रमिक लागतों के अलग-अलग भाग निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक न्यायसंगत सूत्र निम्नानुसार है:-
 - (क) श्रमिकों की कुल संख्या (-) तटीय प्रहस्तन श्रमिक = अयस्क प्रहस्तन श्रमिक (सकल)
 - (ख) अयस्क प्रहस्तन श्रमिक (सकल) (-) अन्तर परिवर्तनीय श्रमिक = अयस्क प्रहस्तन श्रमिक (निब्वल)
 - (ग) अयस्क प्रहस्तन श्रमिक (निब्वल) (-) किसी विशेष अयस्क के लिए लगाए श्रमिक = अतिरिक्त श्रमिक
 - (घ) विशेष अयस्क के लिए लगाए गए श्रमिकों की लागत तैनाती की अवधि से संबंधित अयस्क पर पूरी-की-पूरी लगानी होगी और वर्ष की शेष अवधि के लिए श्रमिकों की लागत उपर्युक्त (ग) के अनुसार अतिरिक्त श्रमिकों की लागत में जोड़नी होगी।
 - (ङ.) अतिरिक्त श्रमिकों की लागत को पूरे वर्ष के लिए सम्पूर्ण अयस्क यातायात (मात्रा) में विभाजित करनी होगी।
- (iii) जैसाकि यह प्राधिकरण पिछली अवधियों पर विचार कर रहा था, इस मॉडल को लागू करते समय पृष्ठभूमि (पश्च भास) का लाभ उपलब्ध था और इसलिए परिकलन "श्रमिक दिवसों" के आधार पर किया गया था न कि "श्रमिकों की संख्या" के आधार पर।

4.1. ऐसी ही परिस्थितियों में मैग्नीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार से संबंधित उपलब्ध एक पिछली घटना के आधार पर पोत परिवहन मंत्रालय ने 1992 के बाद की अवधि में विशा.प.न्यास में मैग्नीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार के समुचित दरमान सुनिश्चित करने के लिए प्रकरण इस प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया है और जिस दिन माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का पोत परिवहन मंत्रालय को आदेश है (अर्थात् 17 मई 2004) उस दिन के बाद से 4 माह की अवधि के भीतर इस प्रकरण को निपटा देने का निदेश दिया है।

4.2. चूंकि पोत परिवहन मंत्रालय का आदेश, उन विधिक प्रावधानों के बारे में स्पष्ट नहीं था जिनके अन्तर्गत यह प्रकरण टीएएमपी को भेजा गया था। इस प्राधिकरण ने पोत परिवहन मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में पोत परिवहन मंत्रालय के आदेश से उभरने वाले बिन्दुओं और इस प्रावधान को कि प्राधिकरण, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 48, 49 और 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संदर्भित प्रकरण में पूर्व प्रभाव से दरों को कानूनन संशोधित कर सकता है, स्पष्ट किया है।

4.3. पोत परिवहन मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि उसका आदेश माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में था और उसने इस प्राधिकरण को इस मामले में निर्णय लेने के लिए कार्यवाही करने का निदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, टीएएमपी के दिसम्बर, 1999 के आदेश में संशोधन करने हेतु विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत पिछले अभ्यावेदन के संदर्भ में, पोत परिवहन मंत्रालय ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया है।

4.4. पोत परिवहन मंत्रालय के आदेश से उमरने वाली स्थिति विशा.प.न्या. को, उनकी टिप्पणी के लिए, यदि कोई हो सूचित की गई थी। विशा.प.न्या.स से हमें इस संबंध में कोई उत्तर नहीं मिला है।

5.1. इस पृष्ठ भूमि में, 24 अगस्त 2004 को 1992 के बाद की अवधि में मैगनीज अयस्क का प्रहस्तन प्रभार निर्धारित करने के संबंध में एक प्रशुल्क प्रक्रिया आरम्भ की गई थी।

5.2. इस प्राधिकरण के पिछले आदेश में यह विशेष रूप से बताया गया था कि उसमें प्रदत्त मॉडल को 1992 और उससे बाद की अवधि के लिए भी लागू किया जा सकता है। इस स्थिति के मद्देनजर, विशा.प.न्या.स को सलाह दी गई थी कि वह उसी मॉडल का अनुसरण करते हुए, 1992 और उसके बाद की अवधि प्रहस्तन प्रभार के निर्धारण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे। विशा.प.न्या.स से अनुरोध किया गया था कि वह इसके साथ ही प्रस्ताव मेसर्स सरावगी कम्प.प्राइ.लिमि. को उस पर उनकी टिप्पणियों के लिए यदि कोई हो, भेद दे।

6.1. तदनुसार, विशा.प.न्या.स ने अपना प्रस्ताव 1 सितम्बर 2004 को दाखिल कर दिया। वीपीटी द्वारा उठाए गए कुछ मुख्य बिंदु संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

- (i) सरकार के निदेश यह नहीं कहते कि टीएएमपी द्वारा अपने पिछले आदेश में प्रदत्त मॉडल का 1992 से 2003 तक की अवधि में मैगनीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार निर्धारित करने हेतु अनुसरण किया जाए।
- (ii) तथापि टीएएमपी द्वारा प्रदत्त मॉडल, बाहरी बंदर पर मशीनों द्वारा प्रहस्तित लौह अयस्क सहित अयस्क की कुल मात्रा पर अतिरिक्त श्रमिक लागत फैलाने के बिन्दु को छोड़कर, इसे स्वीकार्य है।
- (iii) उसने अपने पिछले तर्क पर पुनः जोर दिया है कि अयस्क प्रहस्तन श्रमिक कार्य बल की रचना खनिज अयस्कों के केवल पारम्परिक (मानवीय) प्रणाली द्वारा प्रहस्तन के लिए की गई है। लौह अयस्क का प्रहस्तन केवल अयस्क प्रहस्तन परिसर सुविधाओं के माध्यम से ही किया जाता है और, अतिरिक्त श्रमिकों की लागत को मशीनों की सहायता से प्रहस्तित लौह अयस्क यातायात (मात्रा) पर फैलाना उचित नहीं होगा।
- (iv) अतिरिक्त श्रमिक लागत के अवयव को लौह अयस्क दर में शामिल करने की कोई गुंजाईश नहीं है क्योंकि इसने 1988-89 तक इस गतिविधि में बहुत घाटा उठाया है और वैध कन्वेयर प्रहस्तन लागत भी नहीं वसूली जा सकी।
- (v) अतिरिक्त श्रमिक लागत को कुल अयस्क मात्रा / यातायात पर फैलाना केवल एक सैद्धांतिक प्रक्रिया रह जाएगी और अतिरिक्त लागत अवयव बिन-वसूली के ही रह जाएगा।

6.2. विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास ने केवल श्रमिकों द्वारा प्रहस्तित अयस्क की कुल मात्रा पर अतिरिक्त श्रमिक लागत को फैलाना छोड़कर, टीएएमपी द्वारा निर्धारित मॉडल में 1992 और उसके बाद की अवधि में मैगनीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार परिकलित करते हुए विस्तृत लागत पत्र प्रस्तुत किया है। तदनुसार, विशा.प.न्या.स द्वारा प्रस्तावित दरें निम्नानुसार हैं:

वर्ष	प्रस्तावित दर प्रति टन (रुपयों में)
1992-93	33.34
1993-94	26.10
1994-95	20.44
1995-96	19.06
1996-97	10.42
1997-98	10.93
1998-99	10.03
1999-00	7.74
2000-01	5.75
2001-02	5.21
2002-03	3.36
2003-04	4.74

3016
3

6.3. विशा.प.न्यास ने पुष्टि की है कि हमारी सलाह के अनुसार विशा.प.न्यास के प्रस्ताव की एक प्रति मेसर्स सरावगी कम्प.(प्राइ.) लिमि. को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दी गई है।

7.1. इस प्रकरण में एक संयुक्त सुनवाई 6 सितम्बर 2004 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में विशा.प.न्यास और मेसर्स सरावगी एंड कम्प. (प्रा.) लिमि. ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की:-

मेसर्स एस.के. सरावगी एंड कम्प. (प्रा.) लिमि.

- (i) 1958 में श्रमिकों के स्थायीकरण के बाद भी, पूर्वी डलाव में, मैन्गनीज़ अयस्क और लौह अयस्क समेत सभी अयस्क श्रमिक ही प्रहस्त करते थे। यह चलन 1986 तक, जब एम जी लोको प्रणाली वापस ली गई थी, चलता रहा। हमें अपने स्वयं के पे-लोडर्स और स्लिंग्स लगाने के लिए कहा जाता था। हमारी लागत लगभग रु. 37/- प्रति मी.ट. आती थी।
- (ii) पिछले प्रकरण की पृष्ठभूमि समझाई जिसमें उच्चतम न्यायालय ने, 1986-92 तक की अवधि के संबंध में 1997 को एक आदेश पारित किया था।
- (iii) उच्चतम न्यायालय और टीएएमपी ने अपने पिछले आदेश में, प्रशुल्क निर्धारण में, मुआवजे की अवधारणा पर जोर दिया था।
- (iv) टीएएमपी के समक्ष अपनी पिछली कार्यवाही में हमने हुकिंग के लिए दोगुने या तीन गुने प्रभार का उल्लेख किया था। विशा.प.न्यास द्वारा थर्मल कोल के लिए लगाई गई दरों के बारे में उस समय हमारे तर्कों और अनुरोधों पर कृपया ध्यान दें।
- (v) टीएएमपी ने पहले ही एक मॉडल निर्धारित किया है। विशा.प.न्यास ने आदेश को चुनौती दी है और उच्च न्यायालय ने आरम्भ में आदेश पर स्थगन-आदेश दे दिया किन्तु बाद में न्यायालय ने हमसे बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद पैसे की वापसी करने के आदेश दिए।
- (vi) उच्च न्यायालय के पिछले आदेश के आधार पर हम, 1992 के बाद की अवधि के लिए रु. 20/- प्रति मी. टन की दर से भुगतान कर रहे हैं।
- (vii) टीएएमपी पहले यह निर्णय किया है कि 1992 के बाद की अवधि में अतिरिक्त श्रमिकों की लागत समस्त यातायात पर फैलाई जानी चाहिए।
- (viii) टीएएमपी द्वारा 1992 पूर्व प्रकरण में पहले ही निर्धारित किए गए सिद्धांत अब भी लागू होने चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

- (i) लौह अयस्क 1965 से अलग से प्रहस्तित की जाती थी। ओएचएल श्रमिकों का लौह अयस्क से कोई लेना देना नहीं था।
- (ii) श्रमिक लागत को पिछले प्रभाव से समविभाजित करने का हमारे पास कोई अवसर नहीं है।
- (iii) श्रमिक लागत का भुगतान हमें करना है। इसलिए, लागत वसूली जानी है।
- (iv) हम, श्रमिक लागत को लौह-अयस्क पर फैलाने के सिवाय, पहले निर्धारित किए गए टीएएमपी मॉडल को स्वीकार करते हैं।

7.2. मेसर्स सरावगी एंड कम्प. (प्रा.) लिमि. ने विशा.पत्तन न्यास के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियाँ, 6 सितम्बर 2003 को हुई संयुक्त सुनवाई में प्रस्तुत कीं। मेसर्स सरावगी एंड कम्प. (प्रा.) लिमि. द्वारा प्रस्ताव के संदर्भ में उभारे गए मुख्य बिंदु संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

- (i) उच्चतम न्यायालय के पिछले आदेश में प्रशुल्क निर्धारण में मुआवजे के सिद्धांत पर जोर दिया गया है।
- (ii) मशीनों की सहायता से प्रहस्तित लौह अयस्क समेत अयस्क की कुल मात्रा पर अतिरिक्त श्रमिक लागत को न फैलाने हेतु विशा.प.न्यास का अनुरोध अतार्किक है।
- (iii) मशीनीकृत अयस्क प्रहस्तन संयंत्र के आरम्भ होने से पहले लौह अयस्क श्रमिकों द्वारा प्रहस्तित होता था जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत पड़ती थी। वास्तव में, मैन्गनीज़ अयस्क (और यहाँ तक कि इससे पहले लौह अयस्क) के यातायात के लिए बिछी छोटी रेल लाइन उखाड़े जाने की अपेक्षा लौह अयस्क के प्रहस्तन में मशीनीकरण के कारण श्रमिक अधिक संख्या में अतिरिक्त हो गए।
- (iv) चूंकि अतिरिक्त श्रमिकों की लागत पत्तन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की लागत का भाग नहीं है, तार्किक रूप से इसे प्रशुल्क निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि, फिर भी, जैसाकि पहले इस प्राधिकरण ने राय व्यक्त की थी, अतिरिक्त श्रमिकों की लागत को गिना ही जाना है तो इस बोझ को समस्त कार्गो मात्रा पर बँट देना, फिर चाहे आयात किए गये या निर्यात किए गए कार्गो की प्रकृति कुछ भी हो।

- (v) विशा. पत्तन न्यास की गई ये प्रस्तुतियाँ कि अतिरिक्त श्रमिक लागत को कुल अयस्क यातायात पर फैलाना एक सैद्धांतिक प्रक्रिया ही रहेगी और कि यह लागत अवयव बिन-वसूले ही रह जाएगा, अतार्किक और अनैतिक है। गैर-सेवा अवयव, प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रभार निर्धारित करने के लिए, वास्तव में, अप्रासंगिक अवयव है। दूसरे, अतिरिक्त श्रमिक लागत की वसूली के संबंध में मशीनों द्वारा या श्रमिकों द्वारा प्रहस्तित लौह अयस्क के बीच कोई भेद नहीं हो सकता।
- (vi) विशा. पत्तन न्यास का यह तर्क कि वह टीएएमपी के मार्गदर्शी के अनुसार अतिरिक्त श्रमिकों की लागत इसलिए नहीं वसूल सकता क्योंकि उसे घाटा हो रहा है, सही स्थिति नहीं है। वास्तव में, पत्तन वर्षानुवर्ष लगातार बड़ी मात्रा में अतिरिक्त राजस्व दिखा रहा है।
- (vii) किसी पूर्वाग्रह के बिना, तथापि इसने यह माना है कि 1988 से 1992 तक की अवधि के लिए प्रहस्तन प्रभार निर्धारित करने हेतु इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सूत्र, 1992 के बाद की अवधि के लिए प्रशुल्क निर्धारण हेतु भी न्यायोचित रूप से अपनाया जा सकता है।
- (viii) इसने यह भी अनुरोध किया है कि, जैसाकि वे पर्याप्त समय के अभाव में गणनाओं का सत्यापन नहीं कर सके, उन्हें विशा.प.न्या. के लागत ब्यौरे पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

7.3. संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी, लौह अयस्क यातायात (मात्रा) पर भी अतिरिक्त श्रमिकों की लागत को फैलाने के मामले में टीएएमपी के 1999 के आदेश की समीक्षा हेतु अपने दावे के समर्थन में, संदर्भित श्रमिक बल के मूल और लौह अयस्क के प्रहस्तन के मशीनीकरण के इतिहास का वर्णन करते हुए, 10 सितम्बर 2004 तक एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुआ था। विशा.प.न्या. इस बात की भी जाँच करने के लिए सहमत हो गया था कि क्या टीएएमपी द्वारा मैग्नीज अयस्क के लिए निर्धारित दर साझा आधार पर लगाई जा सकती है या केवल वादी उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित है।

8. जैसाकि संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया था, विशा.प.न्या. ने दिनांक 7 सितम्बर 2004 और 10 सितम्बर 2004 के अपने पत्रों के द्वारा टीएएमपी के दिसम्बर 1999 के आदेश, अंतरिम स्थगनादेश प्रदान करने वाले आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों और उसके बाद के पहले प्रदत्त स्थगन आदेश को निरस्त करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली, विशा.प.न्या. द्वारा दायर समादेश याचिका की एक प्रति प्रस्तुत की हैं। इसने सूचित किया है कि वह समादेश-याचिका निपटान के लिए अभी भी उच्च न्यायालय में लम्बित है। इसने संशोधित परिकलनों के साथ प्रस्ताव पर निम्नलिखित मुख्य बातें प्रस्तुत की हैं:-

- (i) इसने मशीनों की सहायता से प्रहस्तित लौह अयस्क पर, अतिरिक्त श्रमिक लागत को न फैलाने के अपने पिछले बिन्दु पर पुनः जोर दिया है और अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित बिन्दु प्रस्तुत किए हैं:
 - (क) अयस्क प्रहस्तन संयंत्र भीतरी बंदरगाह में 1965 में आरम्भ किया गया था न कि 1976 में, जैसाकि टीएएमपी के आदेश में उल्लेख किया गया है।
 - (ख) अयस्क प्रहस्तन श्रमिकों (ओएचएल) का विभागीकरण 1964 में किया गया था।
 - (ग) यांत्रिक अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (एमओएचपी) पर कमी भी, श्रमिकों द्वारा प्रहस्तित लौह अयस्क के प्रहस्तन के लिए विचार नहीं किया गया और इस प्रकार टीएएमपी की यह टिप्पणी कि ओएचएल लौह अयस्क के लिए है, सही नहीं है। लौह अयस्क का परम्परागत प्रहस्तन, यद्यपि यह 10.66% था, 1970 में पूरी तरह बंद कर दिया गया था।
 - (घ) अतिरिक्त श्रमिक, साधारण रूप से, अयस्क मात्रा में गिरावट के कारण पैदा नहीं होते बल्कि प्रोत्साहन योजना लागू करने, प्रचालन विधि बदलने जैसे विभिन्न अन्य कारणों से भी पैदा होते हैं।
 - (ङ.) यह अपनी विभिन्न सांविधिक अनिवार्यताओं के द्वारा अपनी श्रम-शक्ति से बंधा हुआ है और यातायात में उतार-चढ़ाव के कारण श्रम-शक्ति को घटाना या बढ़ाना व्यावहारिक तथा सैधानिक रूप से संभव नहीं है।
- (ii) इसने मैग्नीज / अयस्क यातायात पर बोझ को कम से कम करने के लिए अतिरिक्त श्रमिक लागत बांटने के लिए दो विधियाँ सुझाई हैं। पहली विधि वास्तव में प्रहस्तित यातायात पर फैला देने की है और दूसरी विधि आंकड़ों के अनुसार लगाए गए श्रमिकों को दिए गए समय-दर वेतन के आधार पर है। विशा.प.न्या. ने सुझाव दिया है कि इन दोनों में से निम्नतर विधि पर विचार किया जाए।
- (iii) संशोधित परिकलन में इसने हुकमैन, पीस-रेट, डिएलबी से श्रमिकों की परस्पर परिवर्तनीय संख्या आदि से संबंधित आंकड़ों को भी सुधार दिया है। संशोधित परिकलन में ही विशा.प.न्या. ने, जैसाकि पहले परिकलित किया था, अतिरिक्त श्रमिक लागत को मशीनों द्वारा प्रहस्तित लौह अयस्क के अलावा अन्य अयस्क यातायात पर फैला दिया है।

- 9.1. संशोधित परिकलन के साथ विशा.प.न्या. द्वारा तैयार की गई लिखित प्रस्तुतियाँ मेसर्स सरावगी एंड कम्प.(प्रा.) लिमि. को, अपनी टिप्पणियाँ 23 सितम्बर 2004 तक प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ भेजी गई थी। मेसर्स सरावगी एंड कं. प्रा.लिमि. को विशेष रूप से सलाह दी गई थी कि विशा.प.न्या. की गणनाओं का सत्यापन करे और यदि जरूरी समझे तो विशा.प.न्या. से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करे। विशा.प.न्या. को भी सलाह दी गई थी कि वह इस विषय में मेसर्स सरावगी एंड कम्प. (प्रा.) लिमि. के साथ सहयोग करे।
- 9.2. मेसर्स सरावगी एंड कम्प. (प्रा.) लिमि. ने विशा.प.न्या. के संशोधित प्रस्ताव का उत्तर दिया है। इसने सामान्य रूप से उत्त्लेख किया है कि विशा.प.न्या. द्वारा संशोधित प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए आंकड़े उसके मूल परिकलन से भिन्न हैं। इसने विस्तारपूर्वक बताया है कि हुक-मैन के वेतन, आरम्भिक परिकलन की तुलना में बढ़ाए गए हैं। मेसर्स सरावगी एंड कम्प. (प्रा.) लिमि. ने तथापि विशा.प.न्या. द्वारा प्रस्तुत डाटा के सत्यापन पर कोई और टिप्पणी नहीं की है। उसने यह पुनः आग्रह किया है कि उसे मैन्नीज अयस्क के लिए प्रहस्तन प्रभार निर्धारित करने के लिए टीएएमपी द्वारा निर्धारित मॉडल का अनुसरण करने में कोई आपत्ति नहीं है।
10. पोत परिवहन मंत्रालय के निदेशानुसार, इस प्रकरण को 16 सितम्बर 2004 तक निपटारा जाना है। इस प्राधिकरण को यह अच्छी तरह पता है कि इस प्रकरण को निपटाने में उसके पास उपलब्ध समय बहुत सीमित है और इसने तदनुसार, अन्तिम निपटान की शीघ्रता के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। प्रक्रियात्मक मुद्दों को देखते हुए और संबंधित पक्षों को अपनी-अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित समय रेखा का पालन करना संभव नहीं था। अतएव पोत परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वह प्रकरण के निपटाना के लिए निर्धारित समय सीमा को एक माह आगे, अर्थात् 16 अक्टूबर 2004 तक बढ़ा दे। आदेश बढ़ाई हुई समय-सीमा के भीतर ही पारित कर दिया गया है।
- 11.1. इस प्राधिकरण ने दिसम्बर 1999 के अपने पिछले आदेश में मैन्नीज अयस्क के लिए प्रहस्तन प्रभार की गणना के लिए पहले ही एक मॉडल निर्धारित किया था। यह भी संकेत दिया गया था कि इस मॉडल को 1992 के बाद की अवधि के लिए भी लागू किया जा सकता था।
- 11.2. मेसर्स सरावगी एंड कं. (प्रा.) लिमि. को, मैन्नीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार सुनिश्चित करने के लिए पहले निर्धारित मॉडल को 1992 के बाद की अवधि के लिए भी लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है।
- 11.3. विशा.प.न्या. भी पहले निर्धारित किए गए मॉडल के लिए कुछ अयस्क यातायात में मशीनों द्वारा प्रहस्तित लौह अयस्क यातायात को शामिल न करने के अपवाद के साथ सहमत हो गया है।
- 11.4. इस विषय में विशा.प.न्या. का अनुरोध नया नहीं है। वास्तव में, उस विशेष बिन्दु पर, इस प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 1999 में पारित किए गए आदेश को संशोधित करने के लिए विशा.प.न्या. सरकार के पास गया था। सरकार ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है।
- विशा.प.न्या. ने पिछले आदेश को आंध्रप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी थी। इस प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि दिसम्बर 1999 के आदेश का क्रियान्वयन, विशा.प.न्या. द्वारा दायर समादेश याचिका अन्तिम निपटान के लिए न्यायालय में लम्बित होने के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न तो स्थगित किया गया है और न ही दर किनारा किया गया है। व्यावहारिक रूप से, दिसम्बर 1999 का पिछला आदेश अभी भी जीवन्त है और उसमें निहित मॉडल को लागू करते हुए निपटाने को समुचित समझता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकरण में भी, पार्श्व दृश्य (पृष्ठभूमि) का लाभ उपलब्ध है और इसीलिए मॉडल "श्रमिकों की संख्या" की बजाए "श्रमिक दिवस" को गिनती में ले सकता है।
- 12.1. अप्रैल 1993 से अगस्त 2003 तक की अवधि के लिए प्रहस्तन प्रभार की गणना हेतु प्रासंगिक डाटा विशा.प.न्या. द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मेसर्स सरावगी एंड कम्पनी (प्रा.) लिमि. को, विशा.प.न्या. के रिकार्ड से आंकड़ों का सत्यापन करने का एक अवसर प्रदान किया गया है। वास्तव में, विशा.प.न्या. ने भी मेसर्स सरावगी एंड कम्प.(प्रा.) लिमि. को, इस मामले में उनसे सहयोग प्रदान करने की इच्छा व्यक्त करते हुए अलग से एक पत्र लिखा है। तथापि, हमें मेसर्स सरावगी एंड कम्प.(प्रा.) लिमि. से निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई विशिष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि पिछली अवधि से संबंधित डाटा विशा.प.न्या. द्वारा संरक्षित, वास्तविक रिकार्ड्स पर आधारित है, हम विशा.प.न्या. द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को, जिन पर इस विश्लेषण में भरोसा किया गया है, स्वीकार करते हैं।
- 12.2. विशा.प.न्या. द्वारा प्रस्तुत लागत विवरणी में, वर्ष 1998-99 से और उससे आगे के वर्षों में लगाए गए पूल-कर्मचारियों के लिए नई प्रविष्टि भी शामिल है। इन श्रमिकों की वेतन लागत, जो ठेके पर हैं, नियमित ओएचएल की वेतन लागत से कम है। विशा.प.न्या. ने कर्मचारियों की इस श्रेणी की लागत उस सीमा तक ही शामिल की है, जिस सीमा तक इस कार्गो के प्रहस्तन के लिए पूल-कर्मचारियों को

लगाया गया था। चूंकि मेसर्स सरावगी एंड कम्प. (प्रा.) लिमि. की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। पिछली बार निर्धारित मॉडल में पूल श्रमिकों की लागत को शामिल करना स्वीकृत है।

12.3. विशा.प.न्या. ने रिपोर्ट दी है कि मैन्गनीज अयस्क का प्रहस्तन 1 सितम्बर 2003 से विशाखापत्तनम् डॉक लेबर बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया है और इस प्रकार मैन्गनीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार 12 फरवरी 1992 से 31 अगस्त 2003 तक की अवधि के लिए निर्धारित करने की आवश्यकता है। पोत परिवहन मंत्रालय का आदेश भी इस प्राधिकरण से मैन्गनीज अयस्क का इसी अवधि के लिए प्रहस्तन-प्रभार निर्धारित करवाना चाहता है। तथापि विशा.प.न्या. द्वारा प्रस्तुत लागत ब्यौरे वित्तीय वर्ष 1992-93 से अगस्त 2003 तक की अवधि के हैं। वर्ष 1991-92 के लिए मैन्गनीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार इस प्राधिकरण के दिसम्बर 1999 के आदेश के माध्यम से पहले ही निर्धारित किए जा चुके थे। इसलिए, यह दर 13 फरवरी 1992 से मार्च 1992 तक की अवधि में लागू की जाती रहेगी। इसलिए, मैन्गनीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार 1992-93 से अगस्त 2003 तक की अवधि के लिए निर्धारित किए जाने हैं।

13. विशा.प.न्या. में मैन्गनीज अयस्क का युक्तिसंगत प्रहस्तन प्रभार तय करने का मुद्दा मेसर्स सरावगी एंड कम्प. (प्रा.) लिमि. द्वारा उठाया गया था, जो इस क्षेत्र में पत्तन उपयोगकर्ताओं में से एक है। विशा.प.न्या. में मैन्गनीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार के समुचित दरमान निर्णित करने के बारे में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया संदर्भ 1992 के बाद की अवधि के लिए ही है। इसका अर्थ हुआ कि अनुमोदित दरें साझा रूप से लगाई जाएंगी। इस मामले को तदनुसार ही निर्णित किया गया है।

14. ऐसा लगता है कि मैन्गनीज अयस्क के प्रहस्तन के लिए रु. 30/- प्रति मी.टन की वर्तमान दर केन्द्रीय सरकार द्वारा 1992 में अनुमोदित और अधिसूचित की गई थी। इस प्राधिकरण के समक्ष इससे पहले के प्रकरण में, प्रश्न 1986-92 तक की अवधि के लिए दरें निर्धारित करने का था। इस समय शामिल मुद्दा, केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले अनुमोदित दरमान को पिछले प्रभाव से संशोधित करने का है। जब इस विषय में परामर्श किया गया तो पोत परिवहन मंत्रालय ने, 1992 से बाद की अवधि के लिए दरों के निर्धारण हेतु माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में आगे बढ़ने की सलाह दी है। ऐसा है तो, 1992 से बाद की अवधि के लिए निर्धारित दरें, केन्द्र सरकार द्वारा पहले स्वीकृत दरों के अधिक्रमण के रूप में प्रभावित होंगी।

15. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से, यह प्राधिकरण 1992-93 से 31 अगस्त 2003 तक की अवधि में मैन्गनीज अयस्क के लिए प्रहस्तन प्रभार जैसाकि परिशिष्ट -I के रूप में संलग्न विवरण में दिया गया है, निर्धारित करता है, जैसाकि पहले कहा जा चुका है, 13 फरवरी 1992 से 31 मार्च 2003 तक की अवधि के लिए मैन्गनीज अयस्क के प्रहस्तन प्रभार, दिसम्बर 1999 के पिछले आदेशों के प्रावधानों के अनुसार रु. 5.10 प्रति टन होंगे। विशा.प.न्या. को निदेश दिया जाता है कि वह दरमान में तदनुसार पिछले प्रभाव से संशोधन कर ले।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/04-असा.]

1992-93 से 2003-04 (31 अगस्त 2003 तक) की अवधि के लिए मैन्नीज अयस्क के प्रहस्त हेतु दर का निर्धारण

क्र. सं.	विवरण	इकाई	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04
1.	प्रहस्त मैन्नीज अयस्क	टनो में	78497	58534	83331	81737	74085	61309	60341	164351	227281	172554	172250	69499
2.	प्रहस्त अयस्क की कुल मात्रा	टनो में	5586930	5070876	6160813	6355327	6633613	7929881	7465253	7894115	9880180	9497160	11090154	3826908
3.	श्रमिकों की कुल संख्या	श्रमिक दिन	171915	114810	98630	85045	51830	37660	26280	18615	9655	3850	1460	459
4.	सटीम प्रहस्त श्रमिक (एस्सबल)	श्रमिक दिन	33215	25915	16425	13670	9490	4015	2190	1086	730	730	0	0
5.	अयस्क प्रहस्त श्रमिक (ओरचरल) (3-4)	श्रमिक दिन	138700	88695	79205	71175	42340	33945	24090	17520	9125	2920	1460	459
6.	घटाइए: ओरल को अंतर परिकर्तीय	श्रमिक दिन	33271	21276	24845	24448	16576	0	0	0	188	0	0	0
7.	रैम ओरचरल (5-6)	श्रमिक दिन	105429	67419	54569	48727	25764	33945	24090	17520	8937	2920	1460	459
8.	मैन्नीज अयस्क के लिए लागू गैर ओरचरल	श्रमिक दिन	1575	896	1915	1921	1678	1986	924	1728	1150	284	80	30
9.	मैन्नीज अयस्क के लिए लागू गैर पूल कर्मचारी	श्रमिक दिन	0	0	0	0	0	0	636	2286	4009	3420	2156	1108
10.	अन्य अयस्क के लिए लागू गैर ओरचरल	श्रमिक दिन	14067	11073	9890	14741	15171	26965	19272	15792	7767	2048	1380	321
11.	अतिरिक्त ओरचरल (7-8-10)	श्रमिक दिन	89787	55450	42754	30085	8915	4974	3894	0	0	608	0	108
12.	ओरचरल की दैनिक मात्रा दर	रुपये में	102.81	111.17	117.95	128.72	140.00	180.87	226.97	251.57	258.56	266.48	276.25	280.24
13.	पूल कर्मचारियों की दैनिक वेतन दर	रुपये में	-	-	-	-	-	-	75	75	82	100	130	150
14.	मैग. अय. के लिए लागू गैर ओरचरल के वेतन (12 x 8)	रुपये में	161928	99608	225683	247271	234920	299628	209720	434713	297344	70351	22100	8708
15.	12 रुक मैग. के वेतन	रुपये में	33264	22192	52245	45488	39760	43424	56663	178947	278023	185445	132780	63591
16.	ओरचरल के लिए पीक-स्ट	रुपये में	152402	115039	212868	184675	148400	78222	77482	234776	197508	48893	21991	7521
17.	पूल कर्मचारियों के लिए वेतन	रुपये में	0	0	0	0	0	0	47700	171450	328738	342000	280280	166200
18.	मैग. अय. श्रमिकों को लागू (14+15+16+17)	रुपये में	347622	236839	490796	477414	423100	421274	391545	1017486	1102813	646689	457151	248019
19.	अतिरिक्त ओरचरल को लागू (11 X 12)	रुपये में	9231001	6164377	5038559	3689987	1248100	750427	883821	0	0	162020	0	31346
20.	मैग. अय. श्रमिकों की प्रति टन लागू (18/1)	रुपये में	4.37	4.19	5.89	5.84	5.71	8.87	6.49	8.19	4.85	3.76	2.65	3.64
21.	अतिरिक्त ओरचरल की प्रति टन लागू (19/2)	रुपये में	1.65	1.05	0.82	0.81	0.19	0.09	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01
22.	मैग. अय. के लिए प्रति टन कुल लागू (20+21)	रुपये में	6.03	5.24	6.71	6.45	5.90	8.97	6.61	6.19	4.85	3.76	2.65	3.55
23.	20% की दर से अयस्क (22 x 20%)	रुपये में	1.21	1.05	1.34	1.28	1.18	1.39	1.32	1.24	0.97	0.75	0.55	0.71
24.	30% की दर से उपरि खद (22 x 30%)	रुपये में	1.81	1.57	2.01	1.93	1.77	2.09	1.98	1.86	1.46	1.13	0.80	1.06
25.	प्रति टन कुल लागू श्रमिक मैग. अय. के लिए प्र. प्रकर (23+24+25)	रुपये में	9.04	7.86	10.06	9.67	8.85	10.45	9.91	9.29	7.28	5.65	3.96	5.32

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION

Mumbai, the 4th October, 2004

No. TAMP/41/2004-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) and in compliance of the reference No. PR-14019/20/2004-PG dated 23rd August, 2004 made by the Ministry of Shipping, the Tariff Authority for Major Ports hereby decides the case relating to fixation of handling charge for Manganese Ore at the Visakhapatnam Port Trust for the period from 13 February, 1992 to 31 August, 2003 as in the Order appended hereto.

Visakhapatnam Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 1st day of October 2004)

This case is initiated based on the reference No. PR-14019/20/2004-PG dated 23 August 2004 received from the Ministry of Shipping (MOS) relating to fixation of handling charges for manganese ore at the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for the period from February 1992 to August 2003.

2. The MOS in its order has stated that the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh in their Judgement dated 18 March 2004 in Writ Petition Nos. 17423 and 17424 of 1992 has directed the Central Government to consider and decide the appropriate Scale of Rates of handling charges of manganese ore in VPT for the post-1992 after giving an opportunity to the petitioner i.e. M/s. Sarawagi Co. (P) Ltd., as well as VPT.

3.1. It may be relevant to mention that the Central Government under similar circumstances had passed an Order on 2 August 1998 transferring the case relating to fixation of handling charge for manganese ore at VPT for the period 1986-1992 to the TAMP.

3.2. In compliance of the Government Order, this Authority had taken up the case following the usual consultation process and passed an Order on 8 December 1999 disposing of this case. Some of the main principles set by this Authority in the said Order are summarised below:

- (i). The cost of surplus Ore Handling Labour (OHL) is to be reckoned with commonly for all ores including iron ore handled mechanically.
- (ii). The most equitable formula prescribed for determining the respective shares of labour costs is as follows:
 - (a). Total number of Labour (–) Shore Handling Labour = Ore Handling Labour (Gross).
 - (b). Ore Handling Labour (Gross) (–) Interchangeable Labour = Ore Handling Labour (Net).
 - (c). Ore Handling Labour (Net) (–) Labour deployed for any particular Ore = Surplus Labour.
 - (d). The cost of the labour deployed for the particular ore will have to be a charge fully on the Ore concerned for the period of deployment and the cost thereof for the remaining period of the year added to the cost of surplus labour as at (c) above.
 - (e). The cost of the 'Surplus' Labour will have to be spread over the entire ore traffic for the whole year.

30/6 95/2004-3

- (iii). Since this Authority was dealing with past periods, the benefit of hindsight was available while applying this model and hence the computation was done on the basis of 'mandays' and not on 'number of labour'.

4.1. Based on the precedence available in a similar circumstance relating to handling charge for manganese ore, the Ministry of Shipping has transferred the case about deciding the appropriate Scale of Rates of handling charges of manganese ore at the VPT for the post-1992 period to this Authority and has directed to dispose of the case within a period of 4 months from the date of receipt of the Order of Hon'ble High Court of Andhra Pradesh by the MOS (i.e. 17 May 2004).

4.2. Since the Order of the MOS was not clear about the legal provision under which the case was referred to the TAMP, this Authority has highlighted the issues emerging from the said Order to the MOS and also about the presumption that the TAMP can legally modify the rates in the case in reference retrospectively in exercise of its powers available under Section 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963.

4.3. The MOS has confirmed that its order is in pursuance of the Order of the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh and has advised this Authority to proceed with deciding the matter. Further, with reference to the earlier representation made by the VPT to modify the TAMP Order of December 1999, the MOS had taken a decision not to interfere.

4.4. The position emerging from the Order of the MOS was also pointed out to the VPT for their comments if any. We have not received any specific response from the VPT in this regard.

5.1. In this backdrop, a tariff proceeding relating to fixation of handling charge for manganese ore for the post-1992 period was initiated on 24 August 2004.

5.2. The earlier Order of this Authority specifically stated that the model prescribed therein could be applied for the post-1992 period also. In view of this position, the VPT was advised to file a proposal for fixation of handling charge for the post-1992 following the same model. The VPT was also requested to simultaneously forward its proposal to M/s. Sarawagi Co. (P) Ltd., for their comments, if any, thereon.

6.1. Accordingly, the VPT has filed its proposal on 1 September 2004. Some of the main points made by the VPT are summarised below:

- (i). The Government's directive does not state that the model prescribed by the TAMP in its earlier order is to be followed for fixation of handling charge for manganese ore for the period 1992-2003.
- (ii). The model prescribed by TAMP is, however, acceptable to it except the point of spreading the cost of surplus labour to the total ore traffic including iron ore handled mechanically at the outer harbour.
- (iii). It has reiterated its earlier argument that the work force of Ore Handling labour (OHL) has been created exclusively for handling mineral ores through conventional (manual) system. Iron ore is handled through exclusive Ore Handling Complex facilities and, therefore, it may not be appropriate to spread the cost of surplus labour to the Iron ore traffic being handled mechanically.
- (iv). There is no scope to include the element of surplus labour cost to iron ore rate since it had incurred huge losses in this activity till 1988-89 and even the legitimate conveyor handling cost could not be recovered.
- (v). Spreading of surplus labour cost over the total ore traffic will only remain as a notional phenomenon and surplus labour cost element would be left un-recovered.

6.2. The VPT has furnished detailed cost sheet computing handling charges of manganese ore for the post-1992 period in the model prescribed by the TAMP with the exception of spreading the surplus labour cost only to ore traffic handled manually. Accordingly, the rates proposed by the VPT are as follows:

Years	Proposed rate per tonne (in Rs.)
1992-93	33.34
1993-94	26.10
1994-95	20.44
1995-96	19.06
1996-97	10.42
1997-98	10.93
1998-99	10.03
1999-00	7.74
2000-01	5.75
2001-02	5.21
2002-03	3.36
2003-04	4.74

6.3. The VPT has confirmed that as advised by us, a copy of its proposal has also been forwarded to M/s. Sarawagi Co. (P) Ltd., for their comments.

7.1. A joint hearing in this case was held on 6 September 2004 at the office of this Authority. At the joint hearing, the VPT and M/s. Sarawagi & Co. (P) Limited have made the following submissions:

M/s. S.K. Sarawagi & Co. (P) Limited

- (i). Even after decasualisation of labour in 1958, the labours used to handle all ores at eastern dump including manganese ore and iron ore. This continued till 1986 when NG loco system was withdrawn. We were asked to deploy our own pay loaders and slings. Our cost was around Rs.37/- PMT.
- (ii). Explained the background of earlier case in which Hon'ble Supreme Court passed the Order in 1997 relating to the period 1986-92.
- (iii). The Supreme Court and TAMP in its earlier order emphasized the concept of 'quid pro quo' in tariff setting.
- (iv). In the earlier proceeding before TAMP, we had pointed out double or triple charge for hooking. Please take note of our arguments and prayers made then about rates applied by VPT for Thermal Coal.
- (v). TAMP has already prescribed a model. VPT has challenged the Order and the High Court initially stayed the Order but subsequently the Court Order to effect refund of the money after obtaining bank guarantee from us.
- (vi). Post – 1992, we are paying @ Rs.20/- PMT based on earlier Order of High Court.
- (vii). TAMP has earlier held that post-1992, cost of surplus labour should be spread over the entire traffic.
- (viii). The principles already set up by TAMP in pre-1992 case should apply now also. We have no objection.

Visakhapatnam Port Trust

- (i). Iron Ore was handled separately since 1965. The OHL labour had nothing to do with iron ore.
- (ii). We don't have a chance to apportion the labour cost to Iron Ore retrospectively.
- (iii). We have to pay the labour. Therefore, the cost has to be recovered.
- (iv). We accept the TAMP model prescribed earlier except spreading over labour cost to Iron ore.

7.2. M/s. Sarawagi & Co. (P) Ltd., have furnished written comments on the VPT proposal at the joint hearing held on 6 September 2003. The main points made by M/s. Sarawagi Co. (P) Ltd., with reference to this proposal are summarised below:

- (i). In the earlier judgement of the Supreme Court, the principle of 'quid pro quo' has been emphasized.
- (ii). The request of the VPT for not spreading the cost of surplus labour over the total ore traffic including iron ore handled mechanically is illogical.
- (iii). Prior to the commissioning of mechanised ore handling plant, iron ore was handled manually which required large number of labour. In fact mechanization of iron ore handling had resulted in more surplus labour than that caused by dismantling of narrow gauge Railway line for transporting manganese ore (and even iron ore also earlier).
- (iv). Logically the cost of surplus labour should not be taken into account for fixing the tariff as it is not part of the cost of service rendered by the port. If, however, as previously opined by this Authority, the cost of surplus is to be reckoned with, it may be logical to distribute this burden on all cargo traffic irrespective of nature of cargo imported or exported.
- (v). The submissions made by the VPT that spreading surplus labour cost over total ore traffic will remain a notional phenomenon and that this cost element will remain unrecovered is illogical and unethical. A non service element is actually an extraneous factor for determining charges for service rendered. Secondly, there can be no distinction between iron ore handled mechanically or manually as regards recovery of cost of surplus labour.
- (vi). The argument of the VPT that it cannot recover the cost of surplus labour as per the TAMP guidelines since it is sustaining loss is not the correct position. The port is in fact consistently showing huge revenue surplus year after year.
- (vii). Without prejudice, it has, however, agreed that formula prescribed by the Authority for fixation of handling charge for the period 1986 to 1992 can reasonably be adopted for determining tariff for post-1992 period also.
- (viii). It has also requested that opportunity may be given to them to furnish comments on the cost statement of the VPT as they could not verify the calculations for want of sufficient time.

7.3. At the joint hearing, the VPT agreed to furnish a detailed note by 10 September 2004 explaining the origin of labour force in reference and history of mechanization of iron ore handling in support of its claim for a review of the TAMP Order of 1999 in so far as spreading of cost of surplus labour over iron ore traffic also. The VPT has also agreed to examine whether the rate fixed by TAMP for manganese ore is applicable on common basis or only to the litigant users.

8. As decided at the joint hearing, the VPT vide its letter dated 7 September 2004 and 10 September 2004 has furnished copy each of the Writ Petition filed by the VPT challenging the TAMP Order of December 1999, orders of the High Court Of Andhra Pradesh granting interim stay and a subsequent Order vacating this stay granted earlier. It has informed that the Writ petition is still pending before the High Court for disposal. It has also made the following main submission on the proposal along with revised computation.

- (i). It has reiterated its earlier point about not spreading cost of surplus labour on iron ore handled mechanically and has made following points in support of its argument:
 - (a). The Ore handling plant was commissioned in 1965 in the inner harbour and not in 1976 as mentioned in the TAMP Order.
 - (b). The Ore Handling Labour (OHL) was departmentalised in October 1964.
 - (c). Mechanical Ore Handling Plant (MOHP) was never envisaged for handling iron ore handled manually and hence the observation of the TAMP that OHL are meant for iron ore is not correct. Conventional handling of iron ore though meager at around 10.66% was completely stopped during 1970.

- (d). The surplus labour arises not simply due to fall in ore traffic but due to various other factors like introduction of incentive schemes, change in method of operation, etc.
- (e). It is bound by various statutory obligations toward its man power and it is not practically and legally possible to reduce or increase the manpower depending on fluctuation in traffic.
- (ii). It has suggested two methods for sharing surplus labour cost to minimize the burden on manganese/ ore traffic. The first method is to spread it over the actual traffic handled and second is based on time rate wages paid for the workers deployed as per datum. The VPT has suggested that the lower of the two methods may be considered.
- (ii). In the revised computation it has modified the figures relating to wages of hook men, piece rate, number of labour interchangeable to DLB, etc. In the revised computation also the VPT has spread cost of surplus labour over the ore traffic other than iron ore handled mechanically as was computed by it earlier.

9.1. The written submissions made by the VPT along with the revised computation was forwarded to M/s. Sarawagi & Co. (P) Ltd., requesting to offer their comments by 23 September 2004. M/s. Sarawagi & Co. (P) Ltd., have been specifically advised to verify the calculations of VPT and, if necessary, to obtain necessary clarification on data from VPT. The VPT was also advised to be co-operative with M/s. Sarawagi & Co (P) Ltd., in this regard.

9.2. M/s. Sarawagi & Co (P) Ltd., have responded to the revised proposal of the VPT. It has pointed out in a general manner that the figures furnished by the VPT in the revised proposal vary from its original computation. It has illustrated that the wages of hook-men has been increased in comparison to its initial computation. M/s. Sarawagi & Co (P) Ltd., have, however, not made any other comments on verification of the data furnished by the VPT. They have reiterated that they have no objection to follow the model prescribed by the TAMP for fixation of handling charge for manganese ore.

10. As per the direction of the MOS, this case is to be finalised by 16 September 2004. This Authority is well aware of the limited time available in disposing of this case and accordingly has taken all efforts to expedite final disposal. In view of procedural issues and requirement of giving adequate opportunity to parties to represent their case, it was not possible to meet the prescribed deadline. The MOS was, therefore, requested to extend the time limit prescribed for disposal of this case by one more month i.e. up to 16 October 2004. The Order is passed well within the extended time limit.

11.1. This Authority vide its earlier Order of December 1999 had already prescribed a model for calculation of handling charges for manganese ore. It was also indicated that this model could be applied for post-1992 period also.

11.2. M/s. S.K. Sarawagi & Co. (P) Limited have no objection to applying the model prescribed earlier for determining the handling charges for manganese ore for the post -1992 period.

11.3. The VPT has also agreed to the model prescribed earlier but with an exception of not including the iron ore traffic handled mechanically in the computation of total ore traffic.

11.4. The request of VPT in this regard is not new. As a matter of fact, it had approached the Government on the very same point to modify the Order of December 1999 passed by this Authority. The Government had refused to interfere.

The VPT had also challenged the earlier Order in the Hon'ble High court of Andhra Pradesh. From the documents produced in this proceedings, it is clear that the operation of the Order of December 1999 has not been stayed or set aside by the Hon'ble High Court, even though the writ petition filed by the VPT is still pending for final disposal. In effect, the earlier Order of December 1999 still survives and the model prescribed therein cannot be totally ignored now to adopt a new approach. In fact, no new developments have been brought to our notice warranting a totally new

approach to be adopted. That being so, this Authority finds it appropriate to settle the issue in reference by applying the model prescribed in December 1999 Order. It is noteworthy that in this case also, the benefit of hindsight is available and, therefore, the model can reckon with 'man days' and not 'number of labour'.

12.1. The relevant data for calculation of handling charges for the period from April 1993 to August 2003 are furnished by VPT. M/s. S.K. Sarawagi & Co. (P) Limited have been given an opportunity to verify the figures from the records of VPT. In fact, the VPT has also written separately to M/s. S.K. Sarawagi & Co. (P) Limited about their willingness to cooperate with them in this regard. We have not, however, received any specific response from M/s. S.K. Sarawagi & Co. (P) Limited within the stipulated time limit. Since the data pertaining to the past period are based on the actual records maintained VPT, we accept the figures furnished by the VPT which are relied upon in this analysis.

12.2. The cost statement furnished by the VPT includes a new entry for pool workers deployed from the year 1998-99 onwards. The wage cost of this labour who are on contract is less than the wage cost of regular OHL. The VPT has included cost of this category of workers only to the extent the pool workers were deployed for handling this cargo. Since there has been no objection from M/s. S.K. Sarawagi & Co. (P) Limited, inclusion of the cost of pool labour in the model prescribed earlier is accepted.

12.3. The VPT has reported that handling of manganese ore has been shifted to Visakhapatnam Dock Labour Board from 1 September 2003 and hence handling charges for manganese ore is required to be fixed for the period after 12 February 1992 upto 31 August 2003. The Order of the MOS also requires this Authority to fix handling charges for manganese ore for this period. The cost details furnished by the VPT are, however, from the financial year 1992-93 till August 2003. The handling charges for manganese ore for the year 1991-92 had already been fixed vide this Authority's Order of December 1999. This rate will, therefore, continue to apply for the period from 13 February 1992 to March 1992. The handling charges for manganese ore are, therefore, to be prescribed for the period from 1992-93 till August 2003.

13. The issue about fixing reasonable handling charges for manganese ore at VPT has been agitated by M/s. S.K. Sarawagi & Co. (P) Limited, who are one of the port users in this segment. The reference made by the MOS to this Authority is for deciding appropriate Scale of Rates of handling charges of manganese ore at VPT for the post - February 1992 period. This means, the rates approved now will have common application. The matter is decided accordingly.

14. It appears that the existing rate of Rs.30/- PMT for handling manganese ore was approved and notified by the Central Government in 1992. In the earlier proceedings before this Authority, the question was fixing the rates for the period 1986-92. The issue involved now is modifying retrospectively the Scale of Rates approved earlier by the Central Government. When consulted in this regard, the MOS has advised us to go ahead with prescription of rates for the post-1992 in pursuance of the order of the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh. That being so, the rates prescribed now for the post-1992 period will come into effect retrospectively in suppression of the rate earlier approved by the Central Government.

15. In the result, and for the reasons given above, this Authority fixes handling charge for manganese ore for the period 1992-93 to 31 August 2003 as set out in the statement attached as **Annex- I**. As mentioned earlier, the handling charge for manganese ore for the period from 13 February 1992 to 31 March 2003 will be Rs. 5.16 per tonne in terms of the earlier Order of December 1999. The VPT is directed to amend its Scale of Rates accordingly with retrospective effect.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT/III/IV/143/04-Exty.]

Annex - I

FIXATION OF RATE FOR HANDLING MANGANESE ORE FOR THE PERIOD 1992-93 TO 2003-04 (UPTO 31 AUGUST 2003).

Sl.No	Description	Unit	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04 upto August 2003
1	Manganese Ore handled	In tonnes	79497	56534	83331	81737	74085	61309	60341	164351	227281	172554	172250	69499
2	Total quantity of Ores handled	In tonnes	5588930	5870876	6160813	6355327	6633613	7923981	7465253	7984115	9860160	9497160	11090154	3826908
3	Total Number of labour	mandays	171915	114610	95630	85045	51830	37980	26280	18615	9855	3650	1460	459
4	Less: Shore Handling Labour (SHL)	mandays	33215	25915	16425	13870	9490	4015	2190	1095	730	730	0	0
5	Ore Handling Labour (OHL) (3-4)	mandays	138700	88695	79205	71175	42340	33945	24090	17520	9125	2920	1460	459
6	Less: Inter changeable to DLB	mandays	33271	21276	24648	24448	16676	0	0	0	188	0	0	0
7	Balance OHL (5-6)	mandays	105429	67419	54559	46727	25784	33945	24090	17520	8937	2920	1460	459
8	OHL deployed for Manganese ore	mandays	1575	896	1915	1921	1678	1988	924	1728	1150	264	80	30
9	Pool Workers deployed for manganese ore	mandays	0	0	0	0	0	0	636	2286	4009	3420	2156	1108
10	OHL deployed for other ores	mandays	14087	11073	9890	14741	15171	29985	19272	15792	7787	2048	1380	321
11	Surplus OHL (7-8-10)	mandays	89787	55450	42754	30065	8915	4974	3894	0	0	608	0	108
12	Daily Wage Rate of OHL	In Rs.	102.81	111.17	117.85	128.72	140.00	150.87	226.97	251.57	258.56	266.48	276.25	290.24
13	Daily Wage Rate of Pool workers	In Rs.	-	-	-	-	-	-	75	75	82 (w.e.f. 1.1.2001)	100	130 (w.e.f. 1.9.2002)	150
14	Wages of OHL deployed for manganese ore (12 x 8)	In Rs.	161926	99608	225683	247271	234920	299628	209720	434713	297344	70351	22100	8707
15	Wages for 12 Hook men	In Rs.	33284	22192	52245	45468	39780	43424	56863	176547	279023	185445	132780	63591
16	Piece Rate for OHL	In Rs.	152402	115039	212668	184675	148400	78222	77462	234776	197506	48893	21991	7521
17	Wages for Pool workers	In Rs.	0	0	0	0	0	0	47700	171450	328738	342000	280280	166200
18	Cost of manganese ore labour (14+15+16+17)	In Rs.	347622	236839	490796	477414	423100	421274	391545	1017486	1102613	646689	457151	246019
19	Cost of surplus OHL (11 x 12)	In Rs.	9231001	6164377	5038559	3869967	1248100	750427	883821	0	0	162020	0	31348
20	Cost per tonne of manganese ore labour (18/1)	In Rs.	4.37	4.19	5.89	5.84	5.71	6.87	6.49	6.19	4.85	3.75	2.65	3.54
21	Cost per tonne of surplus OHL (19/2)	In Rs.	1.65	1.05	0.82	0.61	0.19	0.09	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01
22	Total cost per tonne for manganese ore (20+21)	In Rs.	6.03	5.24	6.71	6.45	5.90	6.97	6.61	6.19	4.85	3.76	2.65	3.55
23	Leave, pension & other benefits @ 20% (22 x 20%)	In Rs.	1.21	1.05	1.34	1.29	1.18	1.39	1.32	1.24	0.97	0.75	0.53	0.71
24	Overheads @ 30% (22 x 30%)	In Rs.	1.81	1.57	2.01	1.93	1.77	2.09	1.98	1.86	1.45	1.13	0.80	1.06
25	Total Cost per tonne i.e. handling charges for manganese ore per tonne (22+23+24)	In Rs.	9.04	7.86	10.06	9.67	8.85	10.45	9.91	9.29	7.28	5.65	3.98	5.32